

स्वराज इंडिया

दैनिक सांध्यकालीन

रचा इतिहास

राष्ट्रपति मुर्मू
ने पहना
फाइटर
सूट, राफेल
जेट से भीरी
उड़ान



» Pg12

कानपुर, बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
वर्ष: 02, अंक: 287, पृष्ठ: 8+4, मूल्य: ₹ 2/-

इनसाइड बिलहौर: सभासद की बुआ के बेटे की सदिग्ध मौत... » Pg04

पूर्ण कर्जमाफी की लड़ाई, भारत बंद की धमकी

नागापुर ठप: हजारों किसान सड़कों पर!

दूसरे दिन भी एनएच-44 पर 20 किलोमीटर लंबा जाम, बच्चू कडू ने महाराष्ट्र सरकार से वार्ता करने से कर दिया इनकार

जनशक्ति पक्ष के संस्थापक और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बच्चू कडू किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। वह किसानों की मांगों को लेकर महाएलेगार मोर्चा निकाल रहे हैं। मंगलवार रात वह खुद ट्रैक्टर चलाकर हजारों किसानों के साथ नागपुर शहर के बॉर्डर पर पहुंचे। बुधवार सुबह किसानों ने नागपुर-हैदराबाद हाइवे जाम किया।

जानकारी के मुताबिक, बच्चू कडू के कार्यकर्ताओं ने हाइवे के साथ शहर की छोटी सड़कों भी जाम करना शुरू कर दिया है। कांटों वाले पेड़ सड़क पर डालकर गाड़ियों को रोका जा रहा है। इसकी वजह से करीब 25 किलोमीटर तक जाम लगा। आंदोलनकारियों ने 'सात बारा कोरा' (हमारा कर्ज साफ करो) जैसे नारे भी लगाए। कडू ने राज्य सरकार को 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे मानी नहीं गईं तो वह ट्रेन रोकेंगे और भारत बंद करेंगे।

शहर में आवाजाही ठप पड़ी

इस आंदोलन की वजह से हो रहे ट्रैफिक जाम से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से शहर में आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। इस दौरान पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया है।

आम लोगों का भी समर्थन

किसान तक की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आंदोलन को आम लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। किसान संघ ने नासिक, धुले, पुणे, जलगांव, सोलापुर और सतारा समेत प्रमुख प्याज उत्पादक जिलों के जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर नुकसान का सर्वे कर मुआवजा, फ्री बीज वितरण और मदद देने की मांग की है।

अन्नदाता का हल्ला बोल

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो। नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतर गए हैं। पूर्ण कर्जमाफी की मांग को लेकर किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। किसानों का आंदोलन दूसरे दिन बुधवार 29 अक्टूबर को भी जारी रहा। इसकी वजह से शहर का ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके बच्चू कडू किसानों के समर्थन में खुद ट्रैक्टर चलाकर नागपुर पहुंचे। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है।



पूर्व मंत्री कर रहे हैं किसानों का नेतृत्व

आजतक के इनपुट के मुताबिक, प्रहार

बड़ी खुशखबरी

तीस रुपए प्रति कुंतल बढ़ाए दाम, अन्नदाताओं के खिले चेहरे

गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना!

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो। लखनऊ। 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अमी लंबा समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। योगी सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों को ब 71 तोहफा देते हुए पेरार्ड सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के दाम में 30 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से बरोतरी कर दी है। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में चौथी बार गन्ना के दामों में

बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं कि इस नए फैसले के बाद गन्ना किसानों को कितना फायदा होगा।

योगी सरकार ने बुधवार को गन्ना किसानों को ध्यान में रखते हुए बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। सरकार ने 30 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से रेट बढ़ा दिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद अगेती प्रजाति के गन्ने का दाम 400 रुपए कुंतल हो गया है। अभी

तक अगेती प्रजाति का गन्ने का दाम 370 रुपए था। इसी तरह सामान्य प्रजाति के गन्ने पर भी 30 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। सामान्य प्रजाति के गन्ने का दाम पहले 360 रुपए प्रति कुंतल था, जो अब बढ़कर 390 रुपए प्रति कुंतल हो गया है।

इस तरह अगेती और सामान्य प्रजाति के गन्ने पर गन्ना किसानों को भरपूर फायदा होगा। दरअसल, लगातार गन्ना किसानों की ओर से दाम बढ़ाए जाने की मांग चल रही थी। सरकार



ने भी आखिरकार गन्ना किसानों की मांग पर फैसला ले लिया। इस बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान होगा। सरकार के इस निर्णय से न केवल गन्ना किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, बल्कि प्रदेश के ग्रामीण अर्थतंत्र में नई ऊर्जा भी भरेगी।

इस संबंध में यूपी सरकार के गन्ना विकास

एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि योगी सरकार ने एक बार फिर गन्ना किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि गन्ना किसान केवल उत्पादक नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त स्तंभ हैं। लक्ष्मी नारायण ने बताया कि गन्ना किसानों को अब तक 2,90,225 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। साल 2007 से 2017 के बीच सपा और बसपा सरकारों में किसानों को कुल मात्र 1,47,346 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था।

मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 122 चीनी मिलें संचालित हैं, जिससे प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में जहां 21 मिलें औने-पौने दामों पर बेची गई थीं। वहीं सरकार के पारदर्शी प्रबंधन और निवेशोन्मुख नीतियों से इस उद्योग में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है।

कानपुर में 4 नवंबर से घर-घर जाकर शुरू होगा मतदाता सूची का सत्यापन

» चार नवंबर से शुरू होकर चार दिसंबर तक विशेष अभियान चलेगा

» एक जनवरी 2026 से 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नागरिक भी पंजीकरण के पात्र होंगे



» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के तहत बीएलओ (बूटिक लिस्टिंग ऑफिसर) चार नवंबर से चार दिसंबर तक घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य करेंगे। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की वर्चुअल बैठक में दी गई, जिसमें जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने भी भाग लिया।

आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अगुवाई में हुई बैठक में बताया गया कि एक जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने नगर के सभी

पात्र नागरिकों, विशेष रूप से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवाओं, से सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। तैयारी, प्रशिक्षण और मुद्रण का चरण 28 अक्टूबर से तीन नवम्बर तक निर्धारित है। मतदान केंद्रों का

आवश्यक पुनर्गठन चार दिसम्बर तक पूरा किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची नौ दिसम्बर को प्रकाशित होगी। दावे और आपत्तियाँ नौ दिसम्बर से आठ जनवरी तक प्राप्त की जाएँगी और उनका निस्तारण नौ दिसम्बर से 31

जनवरी तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची सात फरवरी को प्रकाशित होगी। जिलाधिकारी ने ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ सहित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग द्वारा जारी आदेशों और परिशिष्टों का गहन अध्ययन कर निर्धारित समयरेखा के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो, इसके लिए घर-घर सत्यापन, नाम जोड़ने, संशोधन और विलोपन की सभी प्रविष्टियाँ अभिलेखीय प्रमाणों के आधार पर शुद्ध और पारदर्शी रूप से दर्ज की जाएँगी। ईआरओ कार्यालयों और निर्धारित सहायता केंद्रों पर आवश्यक सूचना-पुस्तिकाएं, प्रपत्र और मार्गदर्शन उपलब्ध रहेगा।

खुशखबरी: जयपुरिया आरओबी 10 दिन में होगा जनता को समर्पित



» छावनी इलाके में बने 992 मीटर लंबे पुल से जाम से मिलेगी राहत

60 करोड़ रुपये से तैयार पुल से चकेरी एयरपोर्ट और अन्य मार्गों तक आसान पहुंच

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। छावनी इलाके में बने जयपुरिया रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को आगामी 10 दिन में चालू कर दिया जाएगा। इस पुल के चालू होने के बाद शहर के लाखों लोगों को जाम में फंसने से राहत मिलेगी और वे आसानी से लखनऊ, चकेरी

एयरपोर्ट और अन्य प्रमुख मार्गों तक पहुंच सकेंगे। एसेतु निगम के परियोजना प्रबंधक बीके सेन का कहना है कि पुल के किनारे एप्रोच रोड का निर्माण अंतिम चरण में है। रोड बनते ही पुल पर राहगीरों और वाहनों का आवागमन शुरू होगा। पुल 992 मीटर लंबा है और इसके निर्माण में लगभग 60 करोड़ रुपये लगे। वर्तमान में एक दिन में करीब 100 ट्रेनें इस क्रॉसिंग से गुजरती हैं, जिससे वाहन जाम में फंस जाते थे। पुल चालू होने के बाद वाहन सीधे जाजमऊ हाईवे से उत्राव होते हुए लखनऊ तक जा सकेंगे।

बाँम्बे हॉस्पिटल

नियर आघू रोड, कानपुर-आगरा हाईवे, अकबरपुर, कानपुर देहात



24 घंटे इमरजेंसी सुविधा

24 घंटे एम्बुलेंस व मेडिकल स्टोर की सुविधा

दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन

हेल्पलाइन नं.: 8355017999, 8858997333

हड्डी के सभी ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी
पित्ताशय की पथरी, फिशर, नासूर
अपेन्डिक्स, प्रोस्टेट, कैंसर की गांठ, भगंदर
हर्निया, हाइड्रोसील, छाती का कैंसर
पेट की चोट व अन्य समस्याएं
बच्चेदानी व अण्डाशय की गांठ
घुटने का प्रत्यारोपण, पाइल्स (बवासीर)



डॉ. सुरेश यादव
डायरेक्टर



लायर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने किया संघर्ष का शंखनाद

कानपुर कचहरी गेट पर अधिवक्ताओं का धरना

निर्मल तिवारी /स्वराज इंडिया

कानपुर। महीनों से चल रही रस्साकसी के बाद अंततः कानपुर पुलिस के कथित अधिवक्ता उत्पीड़न के विरुद्ध लॉयर्स एसोसिएशन की अगुवाई में अधिवक्ताओं का धरना संपन्न हुआ। एक ओर लंबी गर्मी के बाद कानपुर की फिजाओं में सर्द हवा का एहसास हुआ तो दूसरी ओर एक लंबे अरसे से ठंडे से पड़े कानपुर के अधिवक्ताओं के इंकलाबी तेवरों में गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन आम अधिवक्ताओं को बार पदाधिकारियों की अनुपस्थिति सालती रही। तमाम वक्ताओं ने वर्तमान पदाधिकारियों के रवैए पर अपनी पीड़ा भी व्यक्त की।

वर्तमान व पूर्व पदाधिकारियों से लेकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं तक ने अपने संबोधन में जहां पुलिस के रवैए पर नाराजगी जताई वहीं अनुभवी वरिष्ठ जनों ने न्यायिक अधिकारियों के रवैए पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया।

संबोधन के दौरान कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पुलिस को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए सबसे पहले अपने आरोपी अधिवक्ता साथियों की मदद के लिए अनुभवी और वरिष्ठ फौजदारी के विशेषज्ञ अधिवक्ताओं की टीम बनाकर दर्ज मुकदमों में



» कचहरी गेट पर दिनभर चला धरना, जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा

» अधिवक्ताओं ने दिखाए विद्रोही तेवर, बैनर में लिखा दम कितना दमन में तेरे देखा है और देखेंगे

प्रभावी पैरवी पर जोर दिया।

वर्तमान कमिश्नर भी रहे निशाने पर लॉयर्स पदाधिकारियों ने बार-बार अपने संबोधन में कहा पूर्व पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने आश्वासन दिया था कि अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमों की समीक्षा की जाएगी लेकिन वर्तमान कमिश्नर ने उन

अधिवक्ताओं पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई शुरू कर दी जिन पर एक दो ही मुकदमे हैं। जमानत पर छूटते ही जेल गेट पर ही एक अन्य मामले में अनूप शुक्ला को गिरफ्तार किए जाने पर भी वक्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

पुलिसिया रवैया न बदलने पर चरणबद्ध आंदोलन

लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए अधिवक्ताओं पर दर्ज हो रहे मुकदमों और पुलिस द्वारा की जा रही जांच और कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया।

उन्होंने पुलिस द्वारा की जा रही गैंगस्टर की कार्रवाई पर भी प्रश्न



फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं

धरने के बाद अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में सबसे पहली मांग अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लागू करने की है। साथ ही मांग है पिछले 6 महीनों में कानपुर के अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त जस्टिस की अध्यक्षता में गठित एसआईटी द्वारा कराई जाए। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में तीसरी मांग की है कि वर्तमान में कानपुर पुलिस कमिश्नर के तैनात वरिष्ठ अधिकारियों की अधिवक्ताओं के मामलों में भूमिका की जांच एवं समीक्षा उच्च स्तरीय जांच आयोग गठित कर कराई जाए। चौथी मांग है अधिवक्ताओं पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं।

उठाते हुए कहा बहुत से मामलों में अधिवक्ताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज नहीं हुई।

बल्कि पुलिस ने जांच में उनके नाम बढ़ाए हैं।

धरने का संचालन कर रहे

लायर्स संगठन के महामंत्री राजीव यादव ने पत्रकारों को बताया कि तमाम वर्तमान पूर्व पदाधिकारियों के साथ ही वरिष्ठ व आम अधिवक्ताओं से चर्चा के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

समाजसेवी के निधन पर मंत्री राकेश सचान ने दी श्रद्धांजलि

सड़क हादसे में हो गया था समाजसेवी प्रहलाद सचान का निधन

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। पुखराया कस्बे में पटेल चौक पर सोमवार को एक तेज रफ्तार डम्पर ने स्कार्पियो और बाइक से टकरा कर भीषण हादसा हो गया था। इसमें स्कार्पियो सवार चार लोगों में एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि जरेलापुर निवासी समाजसेवी प्रहलाद सचान डम्पर के नीचे दब गए और उनका निधन हो गया।

समाजसेवी सचान की अंतिम यात्रा जरेलापुर से हलिया घाट, मूसानगर तक निकाली गई, जिसमें हजारों नागरिक और सर्वदलीय नेता शामिल हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश



सचान भी उपस्थित रहे और श्रद्धांजलि अर्पित की स्थानीय लोगों और नेताओं ने कहा कि पटेल चौक हमेशा भीड़भाड़ वाला है और

ओवरब्रिज न होने के कारण हादसे होते रहते हैं। इस घटना ने ओवरब्रिज की पुरानी मांग को फिर गति दे दी है।

किशोर ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, परिजनों से पूछताछ

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर। वाजिदपुर जल निगम कॉलोनी में एक किशोर ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता काम पर और बहनें मंदिर गई थीं। पुलिस ने मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया है और परिजनों से पूछताछ के बाद भी आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। कानपुर में जाजमऊ थाना क्षेत्र के वाजिदपुर जल निगम कॉलोनी में 13 वर्षीय किशोर ने बुधवार को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान पिता काम पर और दोनों बहनें मंदिर दर्शन करने के लिए गई थीं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। वाजिदपुर जल निगम कॉलोनी निवासी अरविंद कुमार राजपूत जल निगम में

संविदा के पद पर कार्यरत है।

उनके परिवार में बेटा शिवा (13) उर्फ गोलू, दो बेटे रश्मि कुमारी और रुही राजपूत हैं। बुधवार सुबह पिता अरविंद काम पर गए थे, जबकि उनकी दोनों बेटियां महाराजपुर के ब्रह्मदेव मंदिर दर्शन करने गई थीं। तभी गोलू ने खुद को अकेला पाकर कुर्सी के सहारे दुपट्टे से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। दोनों बहनें जब वापस घर आईं, तो गेट का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलने पर लोगों की मदद से गेट तोड़ा गया। भाई का शव फंदे से लटका देख चीख पड़ी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

सभासद की बुआ के बेटे की संदिग्ध मौत

परिजनों की सहमति से मुख्य गेट काटकर कमरे तक पहुंची पुलिस

सुबह कमरे से देर तक बाहर न निकलने पर खुला राज



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। वार्ड नंबर 16 के सभासद काति राठौर के घर बुधवार की सुबह माहौल उस समय मातम में बदल गया। जब सभासद पति की बुआ के बेटे नंदू राठौर (48 वर्ष) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव कमरे में फांसी के फंदे से झूलता मिला, जिससे परिवार में कोहराम मच गया।

सभासद पति अमित राठौर ने बताया कि नंदू राठौर बचपन से बिल्हौर में ही रह रहा था। वह पेशे से ट्रक ड्राइवर था और कुछ दिन पहले ही दिवाली पर घर लौटा था। परिवार के मुताबिक वह पूरी तरह सामान्य था और किसी बात की चिंता नहीं करता दिख रहा था।

बुधवार सुबह जब वह लंबे समय तक कमरे से बाहर नहीं आया, तो परिजनों ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब न मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते

ही चौकी इंचार्ज प्रेमवीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों की सहमति से मुख्य गेट काटा गया और अंदर पहुंचने के लिए दो दरवाजे खोले गए। कमरे में नंदू राठौर का शव फांसी के फंदे से झूलता मिला। कस्बा इंचार्ज प्रेमवीर सिंह ने बताया

कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के कारणों की जांच संदिग्ध परिस्थितियों में हर पहलू से की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पल्लवी क्लासेज में पुलिस ने पढ़ाया साइबर सुरक्षा का पाठ

छात्रों को बताए ऑनलाइन ठगी से बचाव के टिप्स



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों से युवाओं को सतर्क करने के उद्देश्य से बुधवार को पल्लवी क्लासेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिल्हौर थाने से तेज तर्रार दरोगा मोहित यादव और दीवान राजवीर ने छात्रों को साइबर फ्राडम से बचने के तरीके विस्तारपूर्वक समझाए।

मोहित यादव ने कहा कि साइबर अपराधी फर्जी कॉल, ओटीपी, लिंक, सोशल मीडिया हैकिंग और ऑनलाइन गेम्स के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। ऐसे में किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें, और अपनी निजी जानकारी या बैंक डिटेल्स कभी साझा न करें।

उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सतर्कता बड़े नुकसान से बचा सकती है, इसलिए जागरूक रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे और साइबर सुरक्षा से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। इस मौके पर पल्लवी क्लासेज के संचालक विशाल चतुर्वेदी, मनोज चतुर्वेदी, सारिका और रजनी सहित शिक्षक व अभिभावक मौजूद रहे।

कार्यक्रम में हर्ष, कृष्णा, यश, उत्कर्ष, आशुतोष, इच्छा, सौम्या, प्रज्ञा, श्रद्धा, लक्ष्मी, तुंबा, अंशी, हर्षित, अहम सहित कई छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों से कहा कि वे अपने घर और आसपास के लोगों को भी साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करें ताकि समाज में डिजिटल ठगी की घटनाओं को रोका जा सके।

अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

नायब तहसीलदार की अगुवाई में कब्जा मुक्त हुई भूमि



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश और उप जिलाधिकारी डॉ संजीव दीक्षित के आदेश पर सोमवार को प्रशासनिक टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम दयालपुर माजरा बनी में बंजर भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराया। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार शिवराजपुर रंजीत यादव की अध्यक्षता में की गई।

राजस्व टीम के साथ मौके पर राजस्व

निरीक्षक मुकेश दुबे, लेखपाल स्वाति राजपूत, लेखपाल मोहित सचान और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। यह भूमि लंबे समय से अवैध कब्जे में थी, जिसे मुक्त कराया गया है। नायब तहसीलदार रंजीत यादव ने कहा कि अधिकारियों के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई है। भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी का लिया संकल्प

बिल्हौर में चला आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, स्वदेशी अपनाने का आह्वान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बुधवार को बिल्हौर इंटर कॉलेज में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान-युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी के प्रेरक मंत्र के साथ आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी श्री मानवेंद्र सिंह ने युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। युवाओं को लोकल फॉर वोकल का मंत्र अपनाकर स्वदेशी उत्पादों के प्रचार-प्रसार में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

मुख्य अतिथि ने कहा कि स्वदेशी अपनाना सिर्फ आर्थिक मजबूती का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। जब हर घर स्वदेशी बनेगा, तभी सशक्त भारत का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में बिल्हौर विधायक राहुल बच्चा सोनकर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन और संयोजन अनुज अवस्थी तथा हितेश भदौरिया ने किया।

इस अवसर पर मोनु तोमर, नीलकमल चौहान, प्रधान विमलेश मिश्रा, कछु, पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजीत सिंह, और युवा



मोर्चा मंडल अध्यक्ष अमित तिवारी, युवा मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील साहू, जिला अध्यक्ष उपेंद्र पासवान, पूर्व जिला अध्यक्ष कौशल अवस्थी, रामशरण कटियार, सुशील कटियार, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रवीन्द्र सिंह चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनुराग शुक्ला (शिवराजपुर), पूर्व मंडल अध्यक्ष अमित प्रताप सिंह (ककवन), मंडल अध्यक्ष सौरभ शर्मा, ब्लॉक प्रमुख शुभम बाजपेई, पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नवले

मिश्रा, युवा मोर्चा संयोजक सतेन्द्र राठौर, पूर्व नगर अध्यक्ष विक्रम मिश्रा, मंडल अध्यक्ष शुभांशु कटियार, अमरनाथ राजपूत, सानू राठौर सहित भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता व सैकड़ों युवा उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के समापन पर सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करने और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया।

सम्पादकीय

बिहार प्रक्रिया के निष्कर्ष राह दिखाएंगे

उम्मीद के अनुरूप चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे चरण की विधिवत शुरुआत कर दी है। इस चरण में देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीब 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिये केवल तीन माह का समय दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में एसआईआर पर लंबे समय से चले विवादों के मद्देनजर, इस प्रक्रिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खासकर उन राज्यों में जहां विपक्षी दल शासित सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व महाराष्ट्र से ऐसी प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। इसमें दो राय नहीं कि किसी भी लोकतंत्र में पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिये जरूरी हक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

वहीं अयोग्य मतदाता को हटाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर कोई विवाद नहीं माना जा सकता। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया के मद्देनजर पूरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही तत्काल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस बाबत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि आगामी एसआईआर का लक्ष्य मतदाता सूचियों की लंबे समय से लंबित राष्ट्रव्यापी सफाई करना है। ऐसे व्यापक संशोधन देश में समय-समय पर हुए हैं और पिछला संशोधन दो दशक पहले हुआ था। जाहिर बात है कि इस लंबे अंतराल के दौरान मतदाता सूचियों में कई विसंगतियां और त्रुटियां उत्पन्न हो गई होंगी। आयोग ने उदाहरण देते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर

बिहार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में भी मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिये इन सूचियों का प्रमाणीकरण अपेक्षित है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष दलों की आशंकाओं की अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए। साथ ही लोगों में लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया के प्रति उत्साह बना रहना भी जरूरी है। दरअसल, कांग्रेस, माकपा, तृणमूल कांग्रेस आदि दलों को आशंका है कि एसआईआर का इस्तेमाल अवैध मतदाताओं की पहचान की आड़ में लक्षित वास्तविक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिये हो सकता है। जैसे बिहार में हुई कवायद के बाद ज्ञात नहीं है कि यह प्रक्रिया कितने अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने में सफल रही है। निस्संदेह, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा उचित प्रक्रिया-परिश्रम और जनता के विश्वास पर ही टिकी है। निर्विवाद रूप से देश में चुनाव कराने वाली शीर्ष संवैधानिक संस्था की ईमानदारी और निष्पक्षता दोषमुक्त होनी ही चाहिए। चुनाव आयोग को व्यापक सत्यापन, इस प्रक्रिया से जुड़े तमाम हितधारकों के साथ विमर्श और वास्तविक मतदाताओं के मताधिकार को अक्षुण्ण बनाने हेतु एक ठोस निवारण तंत्र विकसित करने की जरूरत है। विपक्षी दलों द्वारा वोट चोरी और अन्य अनियमितताओं के कथित आरोपों का खंडन ठोस सबूतों के साथ किया जाना चाहिए। ताकि जनता में इस प्रक्रिया को लेकर भरोसा कायम रह सके। जैसे एसआईआर के दूसरे चरण का सकारात्मक पक्ष यह जरूर है कि आयोग ने प्रक्रिया के लिये पर्याप्त समय दिया है।

आगे जाता आसियान और पीछे होता सार्क

ज्योति मल्होत्रा

दक्षिण एशिया का शुमार दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के प्रयासों में लगने वाले राजनीतिक अड़ंगे। इस इलाके का सहयोग संगठन दक्षेस खामोश है। नवंबर, 2014 में काठमांडू...दक्षिण एशिया का शुमार दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के प्रयासों में लगने वाले राजनीतिक अड़ंगे। इस इलाके का सहयोग संगठन दक्षेस खामोश है। नवंबर, 2014 में काठमांडू के शिखर सम्मेलन के बाद से उसका कोई सम्मेलन नहीं हुआ है।



अचानक नहीं हुआ है। पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना सरकार के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर को बैंडविड्थ की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश को ट्रांजिट प्वाइंट के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशंस रेग्युलेटरी कमीशन (बीटीआरसी) का कहना था कि भारत को ट्रांजिट प्वाइंट देने से क्षेत्रीय इंटरनेट हब बनने की हमारी क्षमता कमजोर हो जाएगी। भारत का पूर्वोत्तर पहले घरेलू फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का उपयोग करके चेन्नई में समुद्री केबलों के माध्यम से सिंगापुर से जुड़ा हुआ था। चूंकि चेन्नई में लैंडिंग स्टेशन पूर्वोत्तर से लगभग 5,500 किमी दूर है, इसलिए इंटरनेट की गति पर असर पड़ता था। बहरहाल अब भारत पूर्वोत्तर राज्यों में इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरह से अपने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और नए सैटेलाइट सिस्टम के जरिए देगा। इसके लिए भारतनेट प्रोजेक्ट में बड़े सुधार किए गए हैं, जो भारत का अपना डिजिटल नेटवर्क है। साथ ही इसरो के हाई-स्पीड सैटेलाइट नेटवर्क को भी बेहतर तरीके से जोड़ा गया है। इन बदलावों की वजह से अब पूर्वोत्तर राज्यों को तेज और भरोसेमंद इंटरनेट मिलेगा, बिना किसी बाहरी देश पर निर्भरता जताए हुए। भारत और बांग्लादेश के बीच यह महत्वपूर्ण सहयोग था, दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी के महत्व को रेखांकित करता था। यह सहयोग भी एकतरफा नहीं था। भारत भी बांग्लादेश को बैंडविड्थ दे रहा है, जिसे बांग्लादेश अब कम करता जा रहा है। बांग्लादेश ने दूसरे देशों, जैसे सिंगापुर वगैरह से समुद्र में बिछे केबलों के मार्फत बैंडविड्थ आयात शुरू किया है। बात केवल यह नहीं है कि वे अपनी बैंडविड्थ को बढ़ा रहे हैं,

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से और विदेशमंत्री एस जयशंकर स्वयं उपस्थित हुए थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कम्प्युनिटी विजन 2045 को अपनाने के लिए आसियान की सराहना की। कम्प्युनिटी विजन 2045 अगले बीस वर्षों में इस क्षेत्र को एक समेकित समन्वित विकास-क्षेत्र में तब्दील करने की योजना है। अपने आसपास के राजनीतिक माहौल को देखते हुए यह जाहिर होता जा रहा है कि भारत को पूर्व की दिशा में अपनी कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार करना होगा। यह विस्तार हो भी रहा है, पर म्यांमार की अस्थिरता और बांग्लादेश की अनिश्चित राजनीति के कारण कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया के पांच देशों (कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम) के साथ सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने वाले 'गंगा-मीकांग सहयोग कार्यक्रम' में हमें तेजी लानी चाहिए। अब उस दूसरी खबर की ओर आएं, जो इस सिलसिले में महत्वपूर्ण है। भारत के सरकारी स्वामित्व वाले भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने गत 22 अक्टूबर से अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बांग्लादेश से इंटरनेट बैंडविड्थ का आयात बंद कर दिया। इस कदम का सीधा असर पूर्वोत्तर की इंटरनेट कनेक्टिविटी पर पड़ेगा, जो अभी तक बांग्लादेश अखौरा बंदरगाह के माध्यम से आयातित बैंडविड्थ पर निर्भर थी। यह फैसला

बुनियादी मुद्दों को लेकर उपजे आक्रोश के स्वर

प्रदर्शन चल रहे

ज्वाला सिंह दास

एशिया-अफ्रीका-यूरोप में जेन-जी विरोधों-प्रदर्शनों के केंद्र में बुनियादी मांगें हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के बाद अब मेडागास्कर में तख्तापलट हुआ वहीं कई अन्य अफ्रीकी देशों में आंदोलन जारी है। अफ्रीका के मेडागास्कर देश में तख्तापलट हो गया।

हर देश के जेन-जी आंदोलन में एक बात आम है कि वे बुनियादी मांगों के पूरा न होने पर गुस्से में हैं। तकरीबन हर देश में उनका गुस्सा फूटता है और अपने संग तमाम राजनीतिक ढांचों को बहा ले जाता है। यह भी साफ है कि इस युवा पीढ़ी को मौजूदा राजनीतिक तौर-तरीकों यानी फेमवर्क से अपने

मसले हल करने में कोई विश्वास नहीं है। जेन-जी युवाओं के भीतर मौजूदा भ्रष्ट सिस्टम के प्रति नाराजगी कुछ समय से पलती रहती है और अचानक कोई ट्रिगर प्वाइंट होने पर फट जाता है। मेडागास्कर से पहले श्रीलंका, बांग्लादेश और हाल में नेपाल में जिस तरह से युवाओं ने सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के साथ बाकी प्रचलित पार्टियों को किनारे लगाया, वह भी अलग ढंग का राजनीतिक उभार है। सारे जेन-जी विरोधों-प्रदर्शनों के केंद्र में बहुत बुनियादी मांगें हैं- मसलन बेरोजगारी-महंगाई व बेहद भ्रष्टाचार पर गुस्सा, भाई-भतीजावाद पर नाराजगी और खराब सार्वजनिक सेवाओं और बढ़ती गरीबी व असमानता के खिलाफ विद्रोह। लेकिन ये तमाम आंदोलन सत्ता में आमूल-चूल परिवर्तन के बजाय तात्कालिक सत्ता परिवर्तन करने की दिशा अपनाते हैं। इस आंदोलन की पीठ



पर सवार होकर सत्ता पर कब्जा करने वाली ताकतों के चेहरे बहुत बाद में सामने आते हैं और उन्हीं के पास नेतृत्व चला जाता है। अफ्रीका के कई देशों, जैसे दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, नाइजीरिया और केन्या में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और हर जगह कमान युवाओं के हाथ में है। युवा पीढ़ी को मौजूदा राजनीतिक सिस्टम और पार्टियों से दिक्रत है। नेपाल में जैसे नेपो किड्स यानी नेताओं के पेशो-आराम में डूबे बच्चों पर गुस्सा फूटा था, बेरोजगारी पर उबाल आया था और इसमें रैपर्स, हिप-हॉप गायकों ने अहम

भूमिका निभाई, ठीक उसी तरह मोरक्को में युवा आक्रोश सड़कों पर उतरा। मेडागास्कर में तख्तापलट की कहानी देखें तो महज कुछ हफ्तों से युवा मौजूदा निज़ाम के खिलाफ पानी और बिजली की कमी, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। सरकार ने जब इस आंदोलन की दमन किया, तब सेना की कई यूनिटों ने प्रदर्शनकारियों का साथ दिया। राष्ट्रपति के भागने के बाद कमान सेना ने संभाल ली। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस तख्तापलट को असंवैधानिक बताया और अफ्रीकी संघ ने भी इस कदम को खारिज किया। देश को अब एक सैन्य परिषद चलाएगी और सेना के मुताबिक दो साल के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। सवाल है मेडागास्कर में सैन्य तख्तापलट जेन-जी आंदोलन की अपरिपक्वता का परिणाम है और क्या

इससे बाकी देशों में जारी आक्रोश की कोई कड़ी मिलती है। अफ्रीका के ही एक दूसरे देश- मोरक्को में भी चल रहा है जबर्दस्त आंदोलन। मोरक्को के युवा खुद को जेन-जी 212 कहते हैं। वहां स्वास्थ्य सेवाओं की भयानक हालत और महिलाओं की मौतों ने आक्रोश को भड़काया। युवाओं ने टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे माध्यमों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन समर्थन जुटाया और बड़ी लामबंदी 3 अक्टूबर से शुरू की। आंदोलनकारी कहते हैं कि उनका किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ाव नहीं है। वे प्रधानमंत्री के इस्तीफे और अपने गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग लेकर सड़क पर हैं। जेन-जी मोरक्को सरकार की फिजूलखर्ची से नाराज हैं, 2030 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए देश भर में भारी लागत से स्टेडियम और लगजरी होटल बनाए जा रहे हैं,

बुजुर्ग मां को बेटे-बहू ने घर से निकाला, पेंशन और मोबाइल भी छीना

» डीएम ने कराई सुलह, बेटे ने मानी गलती

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के जनता दर्शन में एक वृद्धा ने बेटे और बहू पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया। डीएम ने तुरंत बेटे को कार्यालय बुलाया, फटकार लगाई और सुलह अधिकारी की मदद से दोनों में सुलह कराई, जिसके बाद बेटा मां का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले गया।

और बहू पर मारपीट करने और घर से निकालने का आरोप लगा न्याय की गुहार लगाई। डीएम ने कार्यालय में बेटे को बुलाया और फटकार लगाई। इसके बाद बेटा अपनी मां का हाथ पकड़कर घर ले गया। मंगलवार को जिलाधिकारी ने वृद्धा को फोन कर हालचाल भी लिया। बर्बा निवासी वृद्धा ने जिलाधिकारी को बताया कि 25 अक्टूबर की रात उनके बेटे और बहू ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। मोबाइल और आधार कार्ड भी छीन लिया। डीएम ने तुरंत वृद्धा के बेटे को फोन कर कार्यालय बुलवाया। आमने-सामने बातचीत हुई। डीएम ने वृद्धा के बेटे को समझाया। सुलह अधिकारी डॉ. धीरेंद्र दोहरे को दोनों को समझाने के लिए लगाया गया। करीब एक घंटे तक चले मानमनौवल के बाद मां और बेटे में सुलह हो गई और बेटा मां का हाथ पकड़कर घर ले गया।



यूपी पुलिस भर्ती 2025

अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र किए गए अपलोड

» कड़ी सुरक्षा में प्रदेश के 430 परीक्षा केन्द्रों पर होगी लिखित परीक्षा

» 1172 अभ्यर्थियों की फोटो में गड़बड़ी, नवीनतम रंगीन फोटो जरूरी



स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई (गोपनीय), एएसआई (लिपिक) और एएसआई (लेखा) के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा प्रदेश के 430 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए

के लिए परीक्षा 1 नवम्बर 2025 को 10 जिलों में 244 केन्द्रों पर होगी, जबकि पुलिस उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक पदों की परीक्षा 2 नवम्बर 2025 को 10 जिलों में 186 केन्द्रों पर होगी। लखनऊ में दोनों परीक्षाओं के सबसे ज्यादा केन्द्र होंगे। पुलिस भर्ती बोर्ड ने 1172 अभ्यर्थियों की फोटो में गड़बड़ी पाई है। इन अभ्यर्थियों को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो बोर्ड की वेबसाइट से अपलोड करनी होगी

और परीक्षा के दिन एक अतिरिक्त फोटो साथ लानी होगी। परीक्षा 400 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी व कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जानकारी व सामयिक विषय, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, तथा तार्किक व बुद्धिलब्धि परीक्षा शामिल हैं। सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक, कंप्यूटर टाइपिंग और आशुलिपि परीक्षा के बाद अंतिम चयन होगा। भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2 प्रतिशत और महिलाओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।



चित्रकूट कोषागार घोटाले में 11 पेंशनर और 4 बिचौलिये गिरफ्तार

» 43.13 करोड़ रुपये के घोटाले में शुरू हो गई बड़े पैमाने पर कार्रवाई

» ऑडिट और शिकायत से हुआ खुलासा, मुख्य आरोपी की मौत के बाद जांच तेज

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

चित्रकूट। जिले में कोषागार में 43.13 करोड़ रुपये के घोटाले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। एसआईटी और पुलिस ने 11 पेंशनर और 4 बिचौलियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ और मेडिकल जांच के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जेल भेजे गए पेंशनरों में तीन महिलाएं शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक

बिचौलिये पेंशनरों के साथ मिलकर अतिरिक्त पेंशन के नाम पर खातों में रकम भेजवा रहे थे और उसे बंदरबांट कर रहे थे। घोटाला कमला देवी की शिकायत पर उजागर हुआ, जिनके खाते में अचानक 31 लाख रुपये आए।

ऑडिट टीम ने जांच कर कोषागार बुलाया और तब इस भारी घोटाले का पता चला। मुख्य कोषाधिकारी ने पटल सहायक संदीप श्रीवास्तव (अब मृतक), अशोक वर्मा, एटीओ विकास सिंह सचान और रिटायर्ड एटीओ अवधेश प्रताप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 93 पेंशन खातों में रकम भेजे जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने चार कर्मियों को पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया, जिसमें संदीप श्रीवास्तव की अचानक मौत हो गई। अब जांच जारी है और घोटाले में शामिल सभी नामजद और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।

मंडलीय चिकित्सालय का बाबू बना दलाली का डॉक्टर

मौत के कागज़ पर रिश्त की स्याही

» मृतक प्रमाण पत्र के नाम पर रिश्त का आरोप

» अधिवक्ता की शिकायत से मंडलीय चिकित्सालय में मचा हड़कंप,

» वायरल वीडियो में क्लर्क की करतूत कैमरे में कैद

तौर पर उन्होंने कहा पहले व्यवस्था करिए, तभी आवेदन लेंगे। यानी अब मरे हुए की आत्मा को भी कागज़ पर दर्शन के लिए रिश्त देनी होगी।

अधिवक्ता ने पूरे प्रकरण की शिकायत मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) से की है। उन्होंने बताया कि प्रवीण त्रिपाठी संविदा कर्मचारी अनिकेत के ज़रिए आवेदकों से पैसा वसूलते हैं। जो चढ़ावा दे देता है, उसका प्रमाण पत्र तुरंत बन जाता है और जो सवाल पूछता है, उसका आवेदन महीनों तक फाइलों में दम तोड़ता रहता है। घूसखोरी की यह कहानी अब केवल चर्चा तक सीमित नहीं रही। अधिवक्ता और बाबू के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में बाबू त्रिपाठी साफ़-साफ़ फाइल लेने से इंकार करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि अधिवक्ता उनसे पूछ रहे हैं क्या मृतक प्रमाण पत्र भी अब पैसे से मिलेगा? वीडियो सामने आते ही मंडलीय चिकित्सालय में अफसरों के माथे पर शिकन बढ़ गई है।



सीएमओ बोले, शिकायत मिलेगी तो जांच होगी

जब स्वराज इंडिया ने सीएमओ अयोध्या से बात की, तो उनका जवाब उतना ही प्रशासनिक था जितना उदासीन। उन्होंने कहा अभी तक लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत आने पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी आरोप गंभीर हैं, सबूत सामने हैं, पर कार्रवाई की बत्ती अब भी गुल है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब दर्शननगर का मंडलीय चिकित्सालय भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में आया हो। कमी ब्लड रिपोर्ट घोटाला, कमी दवा आपूर्ति में हेराफेरी, अब मृतक प्रमाण पत्र में रिश्त लगता है इस अस्पताल में इलाज नहीं, इंतजाम ज्यादा ज़रूरी है। जब ज़िम्मे में इलाज के लिए रिश्त दी जाती है, और मौत के बाद प्रमाण पत्र के लिए तब समझ लीजिए, सिस्टम अब इंसान नहीं, सौदे कर रहा है।

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। दर्शननगर स्थित मंडलीय चिकित्सालय एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है मौत के कागज़ पर घूस का कारोबार। अधिवक्ता जब मृतक प्रमाण पत्र का आवेदन देने पहुंचे तो बाबू प्रवीण त्रिपाठी ने फाइल थामने से इनकार कर दिया। कथित

दिल्ली में दो बार हुई क्लाउड सीडिंग फिर भी नहीं हो सकी कृत्रिम वर्षा

» आईआईटी कानपुर के विमान से बुराड़ी और मेरठ के बीच दागे गए आठ-आठ फ्लेयर्स

» दिल्ली सरकार फरवरी तक करेगी और परीक्षण, आंकड़ों के आधार पर बनेगी दीर्घकालिक योजना

» प्रमुख संवाददात स्वराज इंडिया

कानपुर/दिल्ली। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बादलों से घिरे आसमान के बीच दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कृत्रिम वर्षा (क्लाउड सीडिंग) के दो परीक्षण किए, लेकिन बारिश नहीं हुई। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों की टीम ने अपने विशेष

सेसना विमान से बुराड़ी और आसपास के क्षेत्रों में सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड यौगिकों से बने आठ-आठ फ्लेयर्स दागे। दोनों परीक्षणों के बावजूद दिल्ली के किसी हिस्से में वर्षा दर्ज नहीं की गई।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे नमी के अलग-अलग स्तरों पर क्लाउड सीडिंग की क्षमता का दूसरा और तीसरा सफल मूल्यांकन बताया। उन्होंने कहा कि राजधानी में फरवरी तक ऐसे और प्रयोग किए जाएंगे ताकि आंकड़ों के आधार पर एक दीर्घकालिक योजना तैयार की जा सके। सिरसा ने बताया कि 23 अक्टूबर को पहले परीक्षण के बाद मंगलवार को मेरठ से उड़ान भरने वाले आईआईटी कानपुर के सेसना विमान ने दिल्ली में प्रवेश किया और बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग, मयूर विहार, सादिकपुर और भोजपुर होते हुए मेरठ लौट आया। प्रत्येक फ्लेयर का वजन लगभग ढाई किलोग्राम था और उनका उपयोग करीब ढाई मिनट तक किया गया। पूरी सीडिंग प्रक्रिया लगभग बीस मिनट चली। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को हवा की दिशा उत्तरी थी और आर्द्रता पचास प्रतिशत से कम थी,



जो कृत्रिम वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति नहीं मानी जाती। बावजूद इसके वैज्ञानिकों ने तकनीकी तौर पर अभियान को सफल बताया और कहा कि यह भविष्य में वर्षा की संभावना का आकलन करने के लिए अहम कदम है।

विश्लेषण रिपोर्ट- तकनीक, खर्च और नतीजे क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे रासायनिक यौगिकों को बादलों में छोड़ा जाता है ताकि उनमें संघनन की प्रक्रिया बढ़े और वर्षा की संभावना बने। इसका उपयोग प्रदूषण नियंत्रण और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा

उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दिल्ली कैबिनेट ने सात मई को पाँच क्लाउड सीडिंग परीक्षणों की मंजूरी दी थी। इस परियोजना की कुल लागत 3.21 करोड़ रुपये तय की गई थी, यानी प्रत्येक परीक्षण की लागत लगभग 64 लाख रुपये रही। आईआईटी कानपुर के सहयोग से मई-जून में ये परीक्षण किए जाने थे, लेकिन मानसून की सक्रियता के चलते इन्हें टालना पड़ा। 23 अक्टूबर को पहला परीक्षण किया गया जिसमें वर्षा नहीं हुई। इसके बाद मौसम अनुकूल न रहने के कारण 29 अक्टूबर का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को दो और परीक्षण किए गए जो तकनीकी दृष्टि से पूरी तरह सफल रहे, हालांकि वर्षा अब भी नहीं हो सकी। दिल्ली सरकार अब फरवरी 2026 तक ऐसे कई और परीक्षण करने की योजना बना रही है ताकि प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लंबे समय के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जा सके। इस पूरी परियोजना से उम्मीद है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कृत्रिम वर्षा एक कारगर विकल्प साबित हो सकती है, बशर्ते कि मौसम की अनुकूलता और तकनीकी निष्कर्ष एक साथ मिलें।

कानपुर देहात फॉलोअप

(गिरदौी ग्राम पंचायत में बड़ा घोटाला उजागर)

ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर लूटी विकास निधि !

स्वराज इंडिया की खुलासे वाली खबर से मचा हड़कंप

चार साल में फर्जी भुगतान कर लाखों रुपए डकारने के आरोप

डीएम तक पहुंचा मामला, शिकायत पर नहीं शुरू हुई अबतक जाँच

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राज्य वित्त और 15वें वित्त योजना के तहत गांवों के विकास के लिए आई धनराशि पर ग्राम प्रधान और सचिव की नजर पड़ गई। कानपुर देहात की मलासा ब्लॉक के गिरदौी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का ऐसा जाल बुना गया कि सरकारी पैसा सीधे प्रधान, उसके परिवार और सहयोगियों के खातों में पहुंचता रहा। अब ग्रामीणों की शिकायत के बाद यह मामला उजागर हुआ है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया है। शिकायत के मुताबिक ग्राम प्रधान ने सचिव की मिलीभगत से खुद को और अपने सगे भाई को मजदूर दिखाकर लाखों रुपये का भुगतान अपने ही खातों में करा लिया। पंचायत भवन में मिट्टी भरवाई के कार्य में प्रधान ने खुद को मजदूर बताया और ₹91,048 की मजदूरी खुद ले ली। यही नहीं, अपने भाई करण सिंह के खाते में भी गांव के कई कार्यों के नाम पर बड़ी रकम ट्रांसफर की गई।

भाई के खाते में हुए भुगतान का ब्यौरा
नंदलाल के खेत से हनुमान मंदिर तक इंटरलॉकिंग - 22,400,
रामप्रकाश के मकान से कीरत सिंह के मकान तक नाली निर्माण - 14,000, होलिका दहन से रामनरेश के दरवाजे तक नाला निर्माण - 30,800, अकबरनगर पंचायत भवन निर्माण - 43,000, विजय के घर से हरिशंकर के



खेत तक नाली निर्माण - 23,400 रुपए खर्च दिखाए गए हैं। वहीं गांव की जनसेवा केंद्र संचालिका नीतू सिंह के नाम पर भी मजदूरी भुगतान किया गया। उन्हें शिव मंदिर से रमेश प्रजापति के घर तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण के नाम पर 24,800, नंदलाल के मकान से हनुमान के खेत तक सड़क निर्माण में 24,400, और अकबरनगर से गढ़िया तालाब तक ₹41,600 का भुगतान किया गया।
विकास के नाम पर हुआ है सिर्फ भ्रष्टाचार
ग्राम पंचायत गिरदौी में विकास के नाम पर केवल कागजों में काम दिखाए गए। जमीन पर कार्य अधूरे या न के बराबर हैं, लेकिन भुगतान पूरा कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन और नालियों में

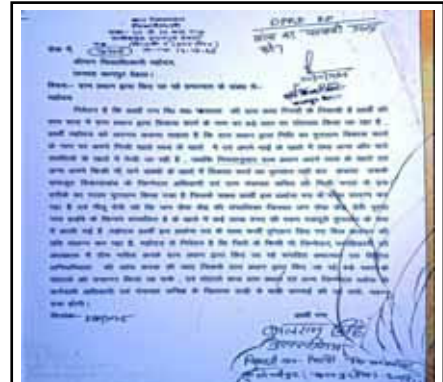
जो काम दिखाए जा रहे हैं, वे वास्तव में हुए ही नहीं गांव के लोगों ने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी कानपुर देहात से की है। शिकायत में कहा गया है कि प्रधान और सचिव की मिलीभगत से करोड़ों की मनरेगा राशि हड़प ली गई है। डीएम ने शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए जांच रिपोर्ट मांगी है।
डीएम का कहना है, ग्राम पंचायत गिरदौी में मनरेगा फंड के दुरुपयोग की शिकायत मिली है। जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम प्रधान हरजीत सिंह यादव ने कहा कि मेरे खिलाफ पहले भी आरोपों को लेकर जांच हो चुकी है, गांव के कुछ लोगों के द्वारा आरोप साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं, शिकायत निराधार हैं।



ग्राम प्रधान हरजीत सिंह के खाते में गए 91 हजार रुपए



यह भुगतान ग्राम प्रधान के भाई करण सिंह के नाम पर करने का आरोप लगाया गया है



गांव वालों के द्वारा की गई है पूरे मामले की शिकायत

वरिष्ठ अधिवक्ता हर्ष यादव के निधन पर अधिवक्ताओं ने दी श्रद्धांजलि

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। लायर्स एसोसिएशन कानपुर के पूर्व कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता हर्ष यादव के आकस्मिक निधन पर अधिवक्ता समाज में शोक की लहर दौड़ गई। जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात के तत्वावधान में जनपद न्यायालय माती स्थित झंडा पार्क में शोकसभा का आयोजन किया गया। शोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव एडवोकेट ने की, जबकि संचालन महामंत्री घनश्याम सिंह राठौर ने किया। अधिवक्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि

दी। बताया गया कि हर्ष यादव का निधन हृदयाघात से हुआ था। शोकसभा में अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हर्ष यादव अधिवक्ताओं के हर संघर्ष में सदैव अग्रणी रहते थे। उनका निधन अधिवक्ता समाज के लिए अपूर्णनीय क्षति है। वे जिंदादिल, मृदुभाषी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि हर्ष यादव लायर्स एसोसिएशन कानपुर में मेरे पिता स्वर्गीय इंद्रपाल सिंह चौहान के अध्यक्ष रहते हुए कोषाध्यक्ष रहे। उन्होंने कानपुर नगर से न्यायालय भवन को कानपुर देहात में स्थापित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष



सम्पत लाल, सुबोध नारायण त्रिपाठी, रमेश चंद्र सिंह गौर, सुलेखा यादव, सर्वेन्द्र सिंह, विश्वनाथ सिंह, जितेन्द्र बाबू, आलोक यादव, राजेन्द्र द्विवेदी, रोहित शुक्ल, नूर आलम, महेंद्र सिंह यादव, अभिषेक सविता, संजय यादव, श्रीप्रकाश पाल, शिवगिरजा शंकर पाल, निर्मल नायक, बलराम सिंह, रविन्द्र मिश्रा, दीपक यादव, अमृत प्रदीप, कमल, योगेन्द्र प्रताप सिंह चौहान, अनूप यादव, धर्मेन्द्र यादव व एस.के. सिंह सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे। सभी ने हर्ष यादव के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी कमी लंबे समय तक अधिवक्ता समाज में महसूस की जाती रहेगी।

हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में लंगड़ा कर दबोचा

» दो दिन पहले हाईवे किनारे मिला था युवक का खून से लथपथ शव, परिजनों ने जताया था हत्या का शक

» मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई, पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी गोली से घायल हुआ आरोपी

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। बरौर थाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान ऋषि कटियार के रूप में हुई है, जो दो दिन पहले युवक की हत्या के



मामले में नामजद था। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में मर्ती कराया है। मुठभेड़ बरौर थाना क्षेत्र के दुर्वासा रोड पर हुई।

पुलिस के अनुसार 26 अक्टूबर की रात अंगदपुर निवासी प्रदीप उर्फ सुक्का (25) की हत्या कर शव कानपुर-इटावा हाईवे किनारे फेंक दिया गया



था। बल्हारामऊ मोड़ के पास खून से लथपथ शव बरामद हुआ था। मृतक के मोबाइल के जरिए पुलिस ने परिजनों को सूचना दी थी। परिजनों ने गांव के ही ऋषि कटियार और ईशू कटियार पर हत्या का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि दोनों युवक प्रदीप को कार में अगवा कर ले गए और उसकी हत्या

कर शव फेंक फरार हो गए। बुधवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि ऋषि कटियार अंगदपुर के पास किसी वारदात की फिराक में घूम रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल भेजा और फरार ईशू

कटियार की तलाश शुरू की है। थाना प्रभारी अमिता वर्मा ने बताया कि दूसरे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर, मामले में परिजनों के बयान उलझ गए हैं। मृतक की मां ममता देवी ने बेटे की मौत को सड़क हादसा बताया है, जबकि अन्य परिजन इसे हत्या मान रहे हैं। परिवार के दो पक्षों में मतभेद के चलते विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक प्रदीप अपने चाचा और बाबा के साथ गांव के भीतर बने मकान में रहता था जबकि उसकी मां सड़क किनारे के घर में। मां-बेटे के बीच गलत संगत और दोस्ती की वजह से झगड़े बढ़ गए थे। इसी विवाद के चलते दोनों पक्षों के बीच तनावनी चल रही थी। पुलिस फिलहाल मामले की गहराई से जांच में जुटी है और फरार आरोपी की तलाश में दबिशें दे रही है।

अकबरपुर में करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं का चल रहा खेल, प्रशासन मौन

» प्रशासनिक अधिकारी तक मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात जनपद के अकबरपुर क्षेत्र में जमीनों पर भू-माफियाओं का खेल चरम पर है। कृषि भूमि पर खुलेआम प्लॉटिंग की जा रही है, जबकि ग्राम समाज,

खलियान और तालाब की जमीनों पर भी दबंगों का कब्जा जारी है। सरकारी कागजों में हेराफेरी कर जमीन हड़पने का यह काला कारोबार अब खुलकर सामने आने लगा है। मामला अकबरपुर कस्बे के हाईवे सर्विस लेन का है, जहाँ आधू गांव की ओर जाने वाले रोड के कॉर्नर पर स्थित करोड़ों की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद गहराता जा रहा है।

इस भूमि को लेकर स्थानीय पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक मौके पर पहुंचे, लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे दोनों पक्ष आज भी असंतुष्ट हैं। एक पक्ष का दावा है कि यह जमीन उसकी निजी संपत्ति है।

जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि हम 70 साल से इस जमीन पर काबिज हैं, अब कागजों में हेराफेरी कर इसे हड़पने की साजिश की जा रही



सरकार और प्रशासन से सीधे सवाल

जब कृषि भूमि पर खुलेआम प्लॉटिंग हो रही है, तो क्या प्रशासन आँख मूंदकर बैठा है? ग्राम समाज और तालाब की जमीनें आखिर किसके संरक्षण में हड़पी जा रही हैं? सरकारी रिकॉर्ड में बार-बार हेराफेरी कैसे हो रही है, क्या इसमें अंदरूनी मिलीभगत नहीं? पीड़ित किसानों और गरीबों की सुनवाई आखिर कौन करेगा? क्या सरकार कानपुर देहात जैसे जिलों में भू-माफियाओं पर कार्रवाई करने से डर रही है?

है। पीड़ित छोटेलाल निवासी अकबरपुर सर्विस लाइन के पास तहसील अकबरपुर ने जिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। छोटेलाल का कहना है कि स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही और अधिकारी मामले को टाल रहे हैं।

सुनासी पंचायत सचिवालय में कार्य बंद, हो रहा खाद का भंडारण

» ग्रामीणों को पंचायत सेवाओं के लिए दूर-दराज के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं

» पंचायत सचिव और प्रधान पर खाद वितरण के नाम पर मनमानी व मोटी रकम वसूलने का आरोप

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिवालय बनाकर ग्रामीणों की सुविधाओं में सुधार करने का दावा किया था, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है। रसूलाबाद विकास खंड के अंतर्गत आने वाली सुनासी ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय का संचालन पूरी तरह ठप है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत भवन में अब ग्राम कार्यों के बजाय डीपी खाद का भंडारण और वितरण किया जा रहा है। पंचायत सचिव और प्रधान कथित तौर पर खाद भंडारण के



बदले मोटी रकम वसूलते हैं। करीब 10 गांवों वाली इस पंचायत में ग्रामीण अपने जरूरी काम, जैसे आय, जाति, निवास, परिवार रजिस्टर, आयुष्मान कार्ड आदि के लिए दूर-दराज के पंचायत कार्यालयों में जाना पड़ता है। पंचायत सहायक लंबे समय से अनुपस्थित हैं और भवन में बैठने के लिए नहीं आते। खंड विकास अधिकारी विपुल सिंह चौहान ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी अब मिली है और जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यदि खाद वितरण के लिए समिति नहीं बनी, तो वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से किसानों को राहत देने का आश्वासन दिया गया है। ग्रामीणों की शिकायत है कि पंचायत भवन के इस ढांचे का मूल उद्देश्य समाप्त हो गया है और सचिवालय सिर्फ भंडारण स्थल बनकर रह गया है।

गड़ों में समा गई सड़क, ग्रामीणों की जान जोखिम में

» नौहानौगांव बंबा पट्टी मार्ग पर जगह-जगह बड़े गड़, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

कानपुर देहात। प्रदेश सरकार मले ही गड़ मुक्त सड़कों का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नौहानौगांव बंबा पट्टी

मार्ग की हालत इस समय बेहद खराब है। सड़क पर जगह-जगह बने गहरे गड़ों के कारण यहां से गुजरना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। क्षेत्र के बिल्डर संपर्क मार्ग से बरिगौ होते हुए नौहानौगांव को जोड़ने वाली यह सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है।

सड़क पर बने गड़ों में पानी भर जाने से वाहन किसलने का खतरा बना रहता है। स्थानीय

ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस मार्ग की मरम्मत की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

खराब सड़क की वजह से आए दिन छोटे-मोटे हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क का पुनर्निर्माण नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करने को बाध्य

होंगे। वहीं, इस संबंध में अवर अनियंता राधेश्याम ने बताया कि सड़क को विशेष मरम्मतकरण योजना में शामिल कर लिया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने ही मरम्मत और निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के %गड़ मुक्त सड़क% के वादों के बीच यह मार्ग सिस्टम की पोल खोल रहा है जहां विकास के दावे गड़ों में समाए नजर आ रहे हैं।



(योगी सरकार की सख्त पैरवी)

माफिया रिजवान जहीर पर कानूनी शिकंजा कसा

» बलरामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में तीन अहम मामलों पर आएगा फैसला, सरकार की प्रभावी कार्यशैली से अपराधियों में हड़कंप

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ/बलरामपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफियाओं पर कानूनी शिकंजा लगाता कसा जा रहा है। इसी कड़ी में टॉप टेन माफिया सूची में शामिल समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के खिलाफ बलरामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में आने वाले दिनों में तीन बड़े मामलों पर फैसले आने वाले हैं। योगी सरकार की ओर से अपर महा अधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह, डीजीसी क्रिमिनल कुलदीप सिंह और एडीजीसी नरेंद्र पांडेय की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत में अब रिजवान जहीर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

आज एमपी-एमएलए कोर्ट में 2021 के जिला पंचायत चुनाव में हुई मारपीट, बलवा, आगजनी और 307 के मामले में फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में रिजवान जहीर, उसका दामाद रमीज नेहमत और

अन्य अभियुक्त शामिल हैं।

वहीं 1 नवंबर को गरीबों की जमीन कब्जाने के मामले में भी कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। इस प्रकरण में रिजवान जहीर के साथ उसकी बेटी जेबा और दामाद रमीज नेहमत आरोपी हैं।

इसके अलावा 5 नवंबर को 302 की धारा में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में भी फैसला आने वाला है। इतना ही नहीं, फिरोज पप्पू हत्या प्रकरण में भी आज सुनवाई पूरी होगी, जिसमें रिजवान जहीर, उसकी बेटी जेबा और दामाद रमीज नेहमत आरोपी हैं। फिलहाल रिजवान जहीर ललितपुर जेल में बंद है।

सरकार की ओर से की जा रही मजबूत और प्रभावशाली पैरवी ने एक बार फिर योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था और अपराधियों पर निर्णायक कार्रवाई की नीति को साबित कर दिया है।

राज्य में अपराध और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ लगातार हो रही इन कानूनी कार्यवाहियों से अपराध जगत में हड़कंप मचा हुआ है।



मानवता की मिसाल बने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह

» अभिभावक की भूमिका में आकर छठवरी महिला को कराया अर्घ्य

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। लक्ष्मण मेला मैदान स्थित गोमती तट पर बुधवार सुबह छठ पर्व का भव्य नजारा देखने को मिला। लाखों महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्र थीं। इसी बीच एक भावनात्मक दृश्य ने सभी के दिलों को छू लिया। एक छठवरी महिला की गोद में दुधमुंही बच्ची थी। समय बीत रहा था, सूर्योदय का क्षण नजदीक था, लेकिन वह पूजा शुरू नहीं कर पा रही थी। बच्ची को गोद से नीचे रखना संभव नहीं था और कोई सहारा भी नहीं मिल पा रहा था। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात

इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की नजर उस महिला पर पड़ी। उन्होंने बिना कुछ कहे स्थिति को समझा और तुरंत आगे बढ़कर बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। पसीने से लथपथ, लेकिन चेहरे पर अपनापन लिए इंस्पेक्टर ने बच्ची को दुलराते हुए महिला को अर्घ्य देने का इशारा किया। महिला ने निश्चित होकर छठी माता की पूजा पूरी की और जब लौटी तो उसकी आंखों में कृतज्ञता और संतोष के भाव थे। इस दृश्य को देखने वाले श्रद्धालु और मौजूद लोग भावुक हो उठे। सभी के जुबां पर एक ही बात थी। इसे कहते हैं खाकी विद डिफरेंस!

चौदह कोसी परिक्रमा के लिए अयोध्या हो गई तैयार

आज रात से लागू हो जाएगा ट्रैफिक डायवर्जन, वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में आस्था का महापर्व चौदह कोसी परिक्रमा शुरू होने को है। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 29 अक्टूबर की रात 10 बजे से 31 अक्टूबर तक या मीड़ समाप्त होने तक विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परिक्रमा मार्ग पर निजी और व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा।

केवल श्रद्धालुओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही अनुमति मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त

पुलिस ने बताया कि परिक्रमा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस, पीएसी और होमगार्ड की तैनाती की गई है।

शहर में सीसीटीवी, ड्रोन सर्विलांस और कंट्रोल रूम से



लाइव

मॉनिटरिंग होगी। सीओ यातायात आशुतोष तिवारी ने अपील की

कि नागरिक निर्धारित डायवर्जन का पालन करें और परिक्रमा मार्ग की ओर अनावश्यक रूप से न जाएं। प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुचारु माहौल बनाना है।

यह रहेगा डायवर्जन रूट

सहादतगंज, शांति चौक, नवीन मंडी और नाका हनुमानगढ़ी से शहर की ओर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।

एनएच-27 से आने वाले वाहनों को देवकाली बाईपास मार्ग से भेजा जाएगा। गोशाईगंज, मकबरा और पूराबाजार तिराहों से अयोध्या की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। अन्तर्जनपदीय वाहनों के लिए देवकाली, लोलपुर और साथी तिराहे के वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं।



राम नगरी में उजाले का पावर कट 45 मिनट के ब्लैकआउट ने हिला दी कुर्सियां

» प्रधानमंत्री के दौरे से पहले राम मंदिर में बिजली गुल

» चेयरमैन की फटकार, अफसरों के सिस्टम की खुली पोल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्याधाम। 14 अक्टूबर की रात राम नगरी अचानक अंधेरे में डूब गई। मगवान राम के दरबार में 45 मिनट तक बिजली गुल रही, और पूरा मंदिर परिसर अंधकार में डूबने के साथ प्रशासन की लापरवाही जगमगाने लगी। यह घटना सिर्फ तकनीकी फॉल्ट नहीं थी बल्कि उस सिस्टम की नंगी तस्वीर थी जो राम मंदिर जैसे विश्वस्तरीय स्थल को भी 24 घंटे बिजली देने की गारंटी नहीं दे पा रहा। इसी अंधेरे की समीक्षा के लिए मंगलवार को बिजली निगम के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल अयोध्या पहुंचे थे और फिर जो हुआ, उसने अफसरों की नींद उड़ा दी।

यह गलती नहीं, अपराध है

समीक्षा बैठक में चेयरमैन गोयल ने पहले ही सवाल दाग दिया राम मंदिर जैसे संवेदनशील स्थल पर 45 मिनट की बिजली कटौती कैसे? सूत्र बताते हैं कि एक अधिकारी ने पारंपरिक खंड पर गलती का ठीकरा फोड़ा, तो चेयरमैन का पारा और चढ़ गया। उन्होंने कहा

यह सिर्फ गलती नहीं, अपराध है। पूरे देश की नजर अयोध्या पर है यहां बिजली कटौती की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की चूक अक्षम्य मानी जाएगी। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया राम मंदिर को 24 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए।

बैठक में चेयरमैन के साथ एमडी मध्यांचल रिया केजरीवाल, निदेशक तकनीकी हरीश बंसल और जिले के सभी अफसर मौजूद थे। कई अधिकारी बिजली आपूर्ति के बजाय जवाब सप्लाई देने में उलझे दिखे।

चेयरमैन ने साफ कहा राम मंदिर सिर्फ उपभोक्ता नहीं, यह पूरे राष्ट्र का विश्वास है। यहां बिजली कटौती का मतलब है भावनाओं पर करंट लगाना। बैठक के बाद चेयरमैन गोयल सीधे कारसेवकपुरम पहुंचे।

जहां उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। दोनों के बीच मंदिर में बिजली व्यवस्था और बैकअप पावर सप्लाई पर विस्तार से चर्चा हुई।

मंदिर में बिजली कटौती की दोबारा नहीं

इसके बाद चेयरमैन ने मंदिर



आशीष गोयल चेयरमैन यूपीपीसीएल



तकनीकी फॉल्ट या प्रबंधन की नाकामी?

चेयरमैन की फटकार के बाद अफसर अब जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे हैं। पारंपरिक विभाग का कहना है कि फ्लाइंग ट्रिप हुई थी, वहीं वितरण खंड का दावा है कि कनेक्शन ओवरलोड था। अंदरखाने की खबर है कि यह मामला अंतरविभागीय तालमेल की नाकामी का नतीजा था। राम मंदिर जैसा संवेदनशील स्थल, जहां प्रधानमंत्री 25 नवंबर को दौरे पर आने वाले हैं, वहां इस तरह का ब्लैकआउट पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है।

चेयरमैन का आदेश, राम मंदिर को प्राथमिकता

मुख्य अभियंता बृजेश कुमार ने बताया कि चेयरमैन ने राम मंदिर को वरीयता के आधार पर बिजली आपूर्ति, बिजलीघरों के निरीक्षण, राजस्व वसूली में सुधार, और बैकअप लाइन के निर्माण के निर्देश दिए हैं। यानी अब अयोध्या में कोई भी अधिकारी अगर लाइन ट्रिप की कहानी सुनाएगा, तो उसे अपनी कुर्सी ट्रिप करने का खतरा रहेगा। वैसे सच कहें तो 45 मिनट का अंधेरा सिर्फ मंदिर में नहीं, सिस्टम में भी उतरा था।

परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया और हर खंड की बिजली लाइन, जनरेटर बैकअप, वोल्टेज नियंत्रण

और सुरक्षा उपकरणों की समीक्षा की। बाद में उन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा से भी भेंट की और बताया

कि अब मंदिर में बिजली कटौती की दोबारा गुंजाइश नहीं बचेगी। पूरे नेटवर्क को डबल बैकअप सिस्टम से जोड़ा जा रहा है।

परिक्रमा मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे, सपा सांसद ने खोली प्रशासनिक तैयारियों की पोल

» 14 कोसी परिक्रमा से पहले सांसद अवधेश प्रसाद का निरीक्षण

» गड्ढों से भरा मार्ग और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर संकट

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो



» सांसद अवधेश प्रसाद ने किया परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण

» जगह-जगह गड्ढे, अधूरे निर्माण और कटीले तारों का जाल

» 24 घंटे में सुधार न हुआ तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर बड़ा संकट

» प्रशासन की तैयारियों पर सपा सांसद ने उठाए गंभीर सवाल

गई है, जिनमें श्रद्धालुओं के उलझकर घायल होने की पूरी आशंका है।

साथ ही कई निर्माण स्थल खुले पड़े हैं सीमेंट, मलबा और बिजली के तार श्रद्धालुओं के लिए

फिसलन भरे जाल बन चुके हैं। सांसद ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर परिक्रमा पथ दुरुस्त नहीं हुआ, तो यह श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ माना जाएगा।

परिक्रमा के नाम पर 'प्रबंधन की परीक्षा'

अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा 30 अक्टूबर को और पंचकोसी परिक्रमा 1 नवंबर को संपन्न होनी है।

इन आयोजनों में लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन तैयारियों की तस्वीर किसी 'आस्था महोत्सव' से ज्यादा 'कर्मचारियों की कसरत' जैसी लग रही है। सपा सांसद के निरीक्षण ने उन तैयारियों की हकीकत उजागर कर दी, जिन्हें प्रशासन पिछले कई दिनों से प्रेस नोटों में पूर्ण बता रहा था। परिक्रमा पथ पर गड्ढे हैं, सड़कों पर तार हैं, और सिस्टम में अंधेरा है। अयोध्या में आस्था चल रही है, पर प्रशासन अब भी ठोकर खा रहा है।

परिक्रमा पर प्रशासन की अग्नि परीक्षा, महापौर आबूधाबी मन्दिर दर्शन में व्यस्त

» अयोध्या में परिक्रमा की तैयारी अधूरी, परिक्रमा पथ में गड्ढे, सफाई अधूरी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या जिला प्रशासन के लिए 14 कोसी और पंच कोसी परिक्रमा की तैयारियां किसी परीक्षा की घड़ी से कम नहीं। चारों ओर अफसर, सफाईकर्मी और इंजीनियर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। सड़कों की धूल, लाइटिंग की गड़बड़ी और मीड प्रबंधन की चुनौतियां सिर पर हैं। परिक्रमा के दिन नजदीक है, मगर कई स्थानों पर नालियां उफन रही हैं, सड़कों गड्ढों से कराह रही हैं। इसी बीच नगर के मुखिया, अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, खुद को परिक्रमा तैयारी से दूर कर संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर निकल गए हैं वो भी सपत्नीक। महापौर ने अपने फेसबुक अकाउंट से यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा आज दुबई और अबू धाबी के हिंदू मंदिर में मगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद।

बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। बिजली के खंडे टिमटिमा रहे हैं और परिक्रमा मार्ग में धूल उड़ रही है, तब महापौर जी दुबई



में क्या सुधार देखने गए हैं? कुछ ने तंज कसा महापौर जी शायद अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'स्वच्छ अयोध्या मिशन' का अनुभव बांटने गए हैं! राजनीतिक गलियारों में भी यह चर्चा गर्म है कि परिक्रमा से ठीक पहले महापौर का विदेश जाना क्या महज संयोग है या नगर निगम की जिम्मेदारियों से कभी काटने की रणनीति? अयोध्या के लोग इस यात्रा को लेकर अब सीधा सवाल पूछ रहे हैं जब रामनगरी में राम के नाम पर परिक्रमा का महासागर उमड़ने वाला है, तब नगर प्रमुख को देश छोड़कर विदेश क्यों जाना पड़ा? कहना गलत न होगा, अयोध्या में परिक्रमा की तैयारी अधूरी है मगर महापौर जी की विदेशी यात्रा पूरी! अब लौटकर आने के बाद वे 'दुबई दर्शन' का अनुभव अयोध्या की सड़कों पर कियाना उतार पाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा।

राष्ट्रपति मुर्मू ने पहना फाइटर सूट, राफेल जेट से भरी उड़ान

पाकिस्तान क तमाचा: जिस पायलट को पकड़ने का पाकिस्तान ने किया था दावा राष्ट्रपति ने उनके साथ खिंचवाई तस्वीर, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर...

रचा इतिहास

» अंबाला, एंजेंसी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार सुबह हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से फ्रांसीसी मूल के राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस ऐतिहासिक उड़ान के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह उड़ान न केवल राष्ट्रपति की साहसिक नेतृत्व शैली का प्रतीक है, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को वैश्विक पटल पर मजबूती से प्रदर्शित करती है।

यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति मुर्मू ने फाइटर जेट की सवारी की हो। इससे पहले 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई-30 एमकेआई



फाइटर विमान में उड़ान भरकर वे फाइटर जेट उड़ाने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्राध्यक्ष बनी थीं। उनसे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ने भी सुखोई-30 एमकेआई में उड़ान भरी थी।

फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल फाइटर जेट को सितंबर 2020 में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन



पर भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को आए पहले पांच राफेल विमानों को 17 स्कवाड्रन गोलडन एरोज में शामिल किया गया। यह बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान वायुसेना की ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

राफेल ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन %ऑपरेशन सिंदूर% में किया, जिसमें 7 मई

को पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्रों में कई आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। इस ऑपरेशन ने जेट की उन्नत तकनीक, सटीक हमले और लंबी दूरी की मारक क्षमता को साबित किया।

भारत ने जिस दौरान पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, उसी



पहले

हरियाणा के अंबाला एयर फोर्स बेस पर उन्हीं शिवांगी सिंह के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और पाकिस्तान के दावों को धराशायी कर दिया।

मशाल के नेतृत्व में एसआईआर पीडीए प्रहरी अभियान का शुभारंभ

हर बूथ पर होगी नियुक्तियां, नाम कटने से रोकने का लिया संकल्प



» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

शोहरतगढ़। समाजवादी पार्टी शिखर समूह के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मणोन्द्र मिश्रा 'मशाल' के नेतृत्व में शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सेखुर्दिया चौराहे पर एसआईआर पीडीए प्रहरी अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत शोहरतगढ़ विधानसभा के सभी बूथों पर एसआईआर पीडीए प्रहरी नियुक्त किए जाने का संकल्प लिया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री लाल जी यादव ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि किसी भी वोट का नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से न कटने पाए। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सतर्कता से ही लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। इस मौके पर श्री मणोन्द्र मिश्रा 'मशाल' ने कहा कि वर्ष 2027 का चुनाव लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री

बनने पर ही खेत-खलिहान और आम जनता के जीवन में खुशहाली आएगी।

उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पीडीए समाज के वोटरों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से गायब कर दिए जाते हैं। इस बार इस गलती को सुधारते हुए न केवल वोट बढ़ाना है, बल्कि वोट चोरी को भी रोकना है।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे मुरलीधर मिश्रा (पूर्व प्रत्याशी), अखिलेश मौर्य (जिला अध्यक्ष, पिछड़ा प्रकोष्ठ), सुरेन्द्र यादव (प्रधान), टिकोरी यादव, श्री अजय चौरसिया (राष्ट्रीय सचिव, छात्र सभा), उमेश यादव (राष्ट्रीय सचिव, यूथ ब्रिगेड), मंजूर खान, श्यामलाल प्रधान, महिबुल्ला, शिवरतन निषाद, मदन निषाद, रामू निषाद, राजेंद्र निषाद, दुर्गेश निषाद, धर्मेंद्र निषाद, रामफेर भारती, कमलेश, श्री रामरतन, श्री प्रकाश चौरसिया, जनार्दन चौहान, कपिल चौधरी, हारून खान, हनुमान जी प्रधान, सुभाष चौरसिया, श्यामलाल राजभर, श्री कमलेश राजभर, श्री जगदेव राजभर, श्री मुबारक सहित अनेक कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

जो पशुओं का चारा खा जाये, वह मनुष्य का हक भी डकार जाता है

बिहार चुनाव: सीएम योगी का राजद पर तीखा हमला, कहा- अब बिहार में सब बा

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

पटना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राकेश रंजन ओझा के पक्ष में जनसभा की। योगी ने कांग्रेस व राजद को निशाने पर लेते हुए कहा कि इन लोगों ने विकास कार्यों को पूरा नहीं किया, क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए, वह मनुष्य का हक भी डकार जाता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ हर नौजवान, गरीब, किसान, माता-बहन को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

उन्होंने स्थानीय भाषा में संवाद की शुरुआत की और मतदाताओं से कमल खिलाने की अपील की। यहां उन्होंने विपक्षी दलों (राजद, कांग्रेस) को खूब धोया। सीएम ने कहा कि इंद्रदेव के आशीर्वाद से यह तय हो गया है कि फिर से एनडीए सरकार बिहार में बनेगी। योगी ने कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबरकर स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़े हैं। अब बिहार से पलायन नहीं होता, बल्कि यहां से निकले इंजीनियर बिहार को प्रगति पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम ने बिहार की प्रतिभा की सराहना की।

उन्होंने कहा कि यहां के नौजवानों में ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले तो बिहार का नौजवान दुनिया को अपनी बुद्धि से आकर्षित रखने का सामर्थ्य रखता है। देश में जहां भी बिहार के युवाओं ने कार्य किया, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार पर भारत



का हर नागरिक गौरव की अनुभूति करता है। उन्होंने बिहार की धरती के महापुरुषों, लोकतंत्र सेनानियों का जिक्र किया और कहा कि यहां का अतीत गौरवशाली रहा, लेकिन राजद का 15 वर्ष और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल कलंक से कम नहीं है। इस दौरान बिहार के नागरिकों को पहचान के संकट से गुजरना पड़ता था। नौजवान पलायन, किसान आत्महत्या, व्यापारी डरा-सहमा रहता था और बेटी-बहन की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई थी।

योगी ने कहा कि बिहार ने जब 2005 में अंगड़ाई ली और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी तो माफिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बिहार नई दिशा की ओर आगे बढ़ा। बिहार में आज वह सब कुछ है, जो 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए। यहां कनेक्टिविटी, बाढ़ प्रबंधन, स्कूली शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज समेत गरीबों के लिए अनेक योजनाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 के पहले परिवारवाद का दंश झेल रहा बिहार अराजकता व गुंडागर्दी की चपेट में आकर माफियाराज का शिकार हो गया था, लेकिन 20 वर्ष में अथक परिश्रम कर नीतीश सरकार ने उसे उभारने में बड़ी मदद की। आज बिहार पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता। जो बिहार के नागरिकों की आकांक्षा है, आज यहां वह सब कुछ है। उन्होंने अपील की कि बिहार के विकास में चल रही रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। डबल इंजन सरकार बुलेट ट्रेन की स्पीड से बिहार की प्रगति को बढ़ा सके, इसके लिए आपका आह्वान करता हूं।

योगी ने कहा कि बिहार में आज विकास व विरासत भी है। राम-कृष्ण-शिव, बाबा महेंद्र नाथ, महर्षि विश्वामित्र, महात्मा बुद्ध, बाबू जगजीवन राम, डॉ. राजेंद्र प्रसाद की परंपरा ही हमारी विरासत है। उन्होंने बिहारवासियों से पूछा कि राम मंदिर बनने से आप खुश हैं, जवाब आया हं।